गोरख पांडेय की कविता

स्व. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की स्मृति में

मरना आसान है, कठिन है जीना
कठिन है जीना, कि एक मौत है भूख
जो कल–कारखानों से ले कर हरे–भरे मैदानों तक
अजगर की तरह पसरी है
दूसरी मौत है गुलामी जिसे कायम रखने के लिये
पूरा–का–पूरा तोपखाना है और तोपची है
सब कुछ को अपने अछोर अंधेरे के गाढ़े पर्दे में छिपाए
जो व्यवस्था कहलाती है
और फ़िर वह मौत तो है ही जो कंगाल मुल्क में बार–बार
महामारी बन जाती है, मरना आसान है, जीना है कठिन
लेकिन इस अछोर अंधेरे के गाढ़े पर्दे को चीरते हुए
तुम आते हो पैरों में सदा चप्पलें डाले
ढीले और चुस्त पाजामे में
माथे पर बल और निगाहों में चुनौती लिये
तुम आते हो, रोती हुई दुलहिनों को चुप कराते हो
सन्नाटा तोड़ने के लिये
काठ की घंटियों से कहते हो–बजो
जहां जा कर आदमी आसानी से खो जाता है
उस शहर से अपने गांव की ओर लौटते हो
और उस कच्ची सड़क की तलाश में भटकते हुए
जो जड़ों की ओर जाती है, तुम मौत को पहचानते हो
भूख और गुलामी के अछोर अंधेरे में फैली हुई
आदमी की और देश की, यानी हर वेश की, मौत को पहचानते हो
अब तुम कुआनो नदी नदी के किनारे हो
जिसमें बाढ़ आ गई है और सब कुछ डूब रहा है
मगर बाढ़ और कीचड़ का इतिहास पार करते हुए
अब तुम उस ज़मीन पर आ गए हो,
जहां से जीवन के सोते फूटते हैं
जहां पत्थरों की छाती पर उग आती है अक्षत दूब
जहां से रोशनी की कोपलें निकलती है
तुम आते हो अपने लोगों के पास
फटे–हाल किसानों और मज़दूरों के पास
तुम अपने गांव लौट आते हो, नक्सलबाड़ी
जो तुम्हारी तरह हम सबका गांव है
लुटी हुई मगर जो लूट का विरोध करने में जुटी हुई
हम सब की बस्ती है
यहां तुम्हारे और सबके चेहरे एक हो गए हैं
और तुम अंधेरे पर हमला शुरू करते हो
दोस्तों को पुकारते, और सिर्फ़ शब्दों से दुश्मनों के छक्के छुड़ाते
आगे बढ़ते हो, भेड़ियों के खिलाफ़ जलाते हो मशाल
और मौत के खिलाफ़ अगली रणनीति तैयार करने में
शामिल होते हो, तुम हमारे बीच होते हो
अपने लोगों, अपनी लय अपने संकल्प
और अपनी तालके बीच होते हो
कि अचानक नहीं होते हो, हम सकते में आ जाते हैं
हमें छोड़ कर तुम, ज़मीन हवा जल और रोशनी में मिल गए हो
हमें सदमा है, कि अभी तो तुम्हें यहां होना था
हज़ार संभवनाओं के साथ, रोशनी और आज़ादी की
ख़ूबसूरत कविताओं और गीतों के साथ
मेहनती मगर सताए हुए लोगों की
उम्मीदों, सपनों और लड़ाइयों के साथ
तुम वहां से बहुत आगे निकल आए थे
जहां से चले थे, मगर तुम्हें अभी और आगे जाना था
अभी कल ही तो नागभूषण पटनायक से मिलना था
और मौत के ख़िलाफ़ उनकी लड़ाई में शामिल होना था
करने थे अभी सुख–दुख के हज़ार चरचे
घटनाओं को अपने विवेक के चरखे पर कातना था
बच्चों में बांटना था नए विचारों का पराग
पीड़ित लोगों में विद्रोह का राग बांटना था
लेकिन तुम नहीं हो, हमने अपना एक सेनापति खो दिया है
हमारी एक मशाल बुझ गई है, हमारे गीतों की एक प्यारी कड़ी टूट गई है
एक गहरे सदमें में तुम्हारी यादों से घिरे, हम यहां खड़े हैं
जहां दूर से आती हुई एक धीमी ललकार, सुनाई पड़ रही है
आगे बढ़ो दोस्तों, आख़िर इस तरह कैसे चल सकता है?
इतनी भूख है इतनी गुलामी है इतनी मौत है
जीवन को चारों ओर दबोचती इतनी मौत
आख़िर इस तरह कैसे चल सकता है?
दोस्तों, आगे बढ़ो, कि यह अछोर अंधेरा हट जाए
कि ज़िंदगी जीते, मौत डर कर सामने न आ पाए
और कभी आए भी तो तुम्हारा आदेश ले कर आए
गरज यह कि जीना आसान हो मरना कठिन हो जाए।

पेज 1 का शेष भाग

कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेंगे : नये सीपी चावला

केवल उतना ही करता है जितना कि बहुत जरूरी हो और यदि उतना किये बगैर ही काम चल जाये तो बल्ले-बल्ले। इसके अलावा उसकी निगाह हमेशा किसी न किसी जुगाड़बाजी से कुछ न कुछ ऊपरी कमाई पर रहती है। अपराधी को पकड़ने की बजाये छोड़ने से जब उसे अधिक लाभ होता हो तो वह अपराधी को क्यों पकड़ेगा? पकड़ भी लेगा तो पैसा लेकर छोड़ देगा।

इक्का-दूक्का नहीं इस तरह के अनेकों उदाहरण 'मज़दूर मोर्चा' में प्रकाशित हो चुके हैं। इस सम्बन्ध में ताज़ातरीन उदाहरण डी एस पी हथीन ज़िले सिंह का हैं जो मेवात के एक बहुत शातिर अम्मू गिरोह को बाकायदा संरक्षण प्रदान करता था। रिवाड़ी रेंज के आई-जी. द्वारा पकड़े जाने पर भी उसे कोई सज़ा नहीं मिली। इस से सिद्ध होता है कि सज़ा देने वाले सक्षम अधिकारी खुद भी काणे हैं। यदि उच्चाधिकारी काणे न हों और पूरी निष्ठा व इमानदारी से काम करते हों तो छोटे मुलाज़िम कभी भ्रष्ट व निकम्मे नहीं हो सकते। कई बार तो छोटे मुलाजिमों को भ्रष्ट ही अपने उच्चाधिकारियों के लिये होना पड़ता है।

पत्रकारों के माध्यम से पुलिस आयुक्त ने जनता को भरोसा दिलाया है कि एक एस एम एस भी यदि कोई उन्हें भेजेगा तो वे तुरंत उसका संज्ञान ले कर उचित एवं पर्याप्त कार्यवाही अमल में लायेंगे। यह सिलसिला पूर्व सी पी कपूर ने भी शुरू तो किया था परन्तु परिणाम कुछ खास निकला नहीं। चावला जी कैसा संज्ञान लेंगे यह तो समय ही बतायेगा लेकिन फ़िलहाल उक्त हत्या व लूट की वारदात तो अपने आप में ही एक महा एस एम एस है, इसका संज्ञान भी उन्होंने ले लिया, लेकिन इसके बाद हुआ क्या? दो चार दिन बाद फ़िर इसी तरह की वारदात हो जायेगी, उसका भी संज्ञान ले कर मौका ए वारदात पर पुलिस अधिकारी रस्म अदायगी कर आयेंगे। इससे आये दिन लुटने पिटने वाली जनता को तो कोई राहत नहीं मिलती।

पुलिस आयुक्त ने शहर में जगह-जगह सी सी टी वी कैमरे लगाने की बात भी कही। इस तरह के कैमरे हाल में हैदराबाद में भी लगे थे जहां आतंकी बम विस्फ़ोट से 16 लोगों की जान लेने में कामयाब रहे। दरअसल इस तरह के कैमरे या अन्य उपकरणों ने स्वयं कुछ नहीं करना होता ये तो केवल उन लोगों की सहायता मात्र कर सकते हैं जिन्होंने कुछ करना होता है। जब पुलिसकर्मियों की नीयत ही कुछ करने की न होगी तो बेचारे कैमरे भी क्या करेंगे, उनकी तो कोई तार भी सलामत नहीं छोड़ेगा।

यातायात नियन्त्रण भी पुलिस की कमाई का एक अच्छा खासा जरिया बन चुका है। डेढ सौ से अधिक संख्या में ट्रैफ़िक पुलिसकर्मी होने के बावजूद सड़क व्यवस्था में कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा। जहां तहां वाहन खड़े हो कर जाम की स्थिति पैदा कर देते हैं। अवैध वाहन, जिनको सड़क पर नज़र नहीं आना चाहिये, धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ते नज़र आते हैं। यह सभी वाहन पुलिस की कमाई का मोटा जरिया हैं।

ज़मीन जायदादों की खरीदो फ़रोख्त में बढते अपराधों के मद्देनज़र सी पी ने पुलिस की एक विशेष कमेटी गठित करने की बात कही है। समझा जाता है कि कोई भी सौदा करने से पहले लोगों को इस कमेटी से सलाह मश्वरा करने को कहा जायेगा। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि जो पुलिस अपना काम तो कर नहीं पा रही वह ज़मीन जायदादों के सौदे की क्या तो पूर्व जांच करेगी और क्या सलाह देगी तथा कौन उसकी सलाह की प्रतीक्षा करता रहेगा? इस मौजूदा व्यवस्था से कोई आशा तो नहीं है, परन्तु इसके सिवा जनता के पास और कुछ नज़र भी नहीं आता।

विज्ञापनों में अपनी पीठ थपथपाती सरकार

हरियाणा सरकार की कोई रूचि इन सेवाओं को चलाने में कभी भी नहीं रही। इसके चलते दिन प्रतिदिन जहां मज़दूरों की संख्या बढ़ती जा रही है वहीं डाक्टरों एवं अन्य स्टाफ़ की संख्या घटती जा रही है। इसी शहर के जिस अस्पताल में कभी 70 डॉक्टर होने थे वहां अब घट कर 17 रह गये हैं जबकि मज़दूरों की संख्या पहले से दोगुणी हो गयी है। ई एस आई निगम के प्रतिमानों के अनुसार जितना स्टाफ़, साजोसामान व दवायें आदि इन अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में उपलब्ध करानी चाहिये उसके लिये राज्य सरकार को करीब 600 करोड़ का बजट बनाना चाहिये जिसका मात्र 72 करोड़ राज्य सरकार को तथा शेष निगम को वहन करना है। परन्तु अपना 60 करोड़ बचाने के लिये राज्य सरकार बजट ही 100 करोड़ का बनाती है। मूर्खों द्वारा चलाई जा रही सरकार यह हिसाब लगाने में भी सक्षम नहीं है कि अपने 60 करोड़ बचाने के चक्कर में निगम से मिलने वाले कितने सौ करोड़ उसने गंवा दिये। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार राज्य की करीब एक तिहाई आबादी ई एस आई सी के दायरे में आ रही है जिसको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध-कराने को निगम तैयार है। इस पूरे मामले का दुखद पहलू यही है कि केन्द्र सरकार मज़दूरों से पैसा वसूले जा रही है और राज्य सरकार उसका सदुपयोग करके उन्हें समुचित लाभ नहीं दे रही। कुल मिला कर, इस सारे खेल में रगड़ा तो मज़दूर ही गया ना।

'हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे'

तो सोनिया एंड कंपनी ने पॉलिटिक्स को कहवाखाना बना दिया और मनमोहन नाम के रोबोट को सत्ता की कमान सौंप दी जो रिमोट से चलता है।

देश एक अजीब ही दौर से गुजर रहा है। साम्राजी गुलामी का नया दौर। अंबानी, मित्तल, टाटा, जैसे पूंजीपति साम्राजी ताकतों के लिये दलालों की भूमिका निभा रहे हैं और तमाम सियासतदां मीर जाफर बनने के लिए तैयार हैं। ये देश को बेच देंगे।

पहले ही देश को न जाने कितने टुकड़ों में बांट डाला। जीते-जागते इंसान को महज एक वोट में बदलने के लिये न जाने कितना ख़ून बहाया। रक्त-रंजित है इतिहास। निरीह जनता का ख़ून बहता रहा है, अभी और बहेगा।

फिर इस भयानक दौर में तो घोटालों को कौन पूछता है। ये तो मामूली बातें हैं।

अगले साल चुनाव होंगे। तमाम दलों के तमाम भेड़िये लीडरान अपने दांतो को और भी धारदार बनाने में लग गए हैं। वहीं, कुछ रंगे सियार रामनामी चादर ओढ़े घूमते दिखाई पड़ने लगे हैं।

देखना है, आने वाले दिनों में कैसे-कैसे तमाशे होते हैं।

एक ज़माना था, आज़ादी मिलने के बाद नेहरू ने समाजवाद का दिवा-स्वप्न दिखाया था और लोग कहने लगे थे-

'गया दौर सममायादारी गया
तमाशा दिखाकर मदारी गया।'

पर आज, शायर अदम गोंडवी कहते हैं,

''जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे।
कमीशन दो तो हिन्दुस्तान को नीलाम कर देंगे।''

मारुति के मज़दूरों का दमन के ख़िलाफ़ संघर्ष जारी

मारुति मज़दूरों द्वारा 21 जनवरी से हरियाणा के चार स्थानों से सप्ताह भर की साइकिल यात्रा निकाल कर 27 जनवरी को रोहतक में रैली की घोषणा की गयी। जत्थें ने जैसे ही मार्च करना शुरू किया और उसको मिल रहे जनसमर्थन ने सरकार के होश फाख्ता कर दिए। मारुति प्रबंधकों की पालतू हरियाणा सरकार ने मज़दूरों का तरह-तरह से उत्पीड़न शुरू कर दिया। रेवाड़ी से निकले जत्थे को मानेसर नहीं जाने दिया। भारी तादाद में मौजूद पुलिस ने जत्थे के लोगों को गिरफ्तार कर उनकी साइकिलों को कैंटर में डालकर उन्हें काफ़ी दूर ले जाकर छोड़ दिया। ताकि वो दुबारा वापस मानेसर-गुड़गांव न जा सकें।

पुलिस ने पानीपत में रुके हुए जत्थे को सभा नहीं करने दी। हर जत्थे पर पुलिस ने भारी दबाव बनाया, डराया, धमकाया। मारुति मज़दूरों के घरों पर फोन किये गए कि वो 27 तारीख की रैली में न जाएं। 24 जनवरी को गुडगांव में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पुलिस ने प्रोविजनल कमेटी के नेता ईमान खान को गिरफ्तार कर लिया। उनका नाम मारुति केस में नहीं था लेकिन पुलिस ने उन्हें 18 जुलाई कांड में झूठा फंसा कर जेल भेज दिया ताकि मज़दूरों का मनोबल टूट जाये, पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में ईमान का कहीं भी नाम नहीं था। उन्हें केवल इसलिये उठाया गया कि वह आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस उनको गिरफ्तार कर मज़दूरों को डराना चाहती है ताकि मज़दूर डरकर आंदोलन बंद कर दें। पुलिस द्वारा 'तफ्तीस जारी है' के नाम पर मज़दूरों के सर पर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटकी है। कि जो भी अगुवाई करेगा उसे उठा लेंगे। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लोकतंत्र कुल मिलाकर मज़दूर वर्ग पर पूंजीपति वर्ग की तानाशाही है। शासन सत्ता के सारे अंग पूंजीपति की सेवा में लगे हुए हैं। मारुति चेयरमैन भार्गव ने घटना के बाद इसे वर्ग संघर्ष बोलकर पूंजिपतियों की तरफ से मज़दूरों के खिलाफ़ युद्ध का एलान कर दिया था। अब देशभर के मज़दूरों पर सवाल है कि वो इसका जवाब अपनी फ़ौलादी एकता से कैसे देते हैं। पुलिस द्वारा की जा रही इन ज्यादतियों के विरोध में मारुति मज़दूरों व उनके सहयोगी संगठनों ने 25 जनवरी को गुडगांव के ऑफिस पर धरना दिया तथा दोषी पुलिस कर्मचारियों को सज़ा की मांग की, सभा में वक्ताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार अब मज़दूरों के सामान्य जनवादी अधिकारों तक का हनन कर रही है। सरकार मज़दूरों से इतनी डरी हुई है कि वो उनकी आवाज तक उठाने के अधिकार को कुचल दे रही है। लेकिन मज़दूरों के हौसले हर दमन से और बढ़ेंगे ही न कि मज़दूर इन दमनकारी सरकारी कदमों से डरेंगे। इतिहास गवाह है कि दमन ने मज़दूर आन्दोलन को और मज़बूत ही किया है। **-नागरिक**

मज़दूर मोर्चा

नियमित पढ़ने हेतु पाठकगण अपने हॉकर से संपर्क करें। जो हॉकर, आपके घरों में दैनिक अखबार डालते हैं, आपके आदेश पर मज़दूर मोर्चा भी डालेंगे। कोई दिक्कत हो तो दीक्षित न्यूज़ एजेंसी से 9811159238 पर संपर्क करें।

'मज़दूर मोर्चा' प्रिंटफोर्ट, नेहरू ग्राउंड पर भी उपलब्ध है।